भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2546
21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

झारखंड में इस्पात क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन

2546. # श्री आदित्य प्रसाद :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झारखंड में इस्पात क्षेत्र में हो रहे निवेश के नवीनतम प्रस्तावों से अवगत है ;

(ख) क्या सरकार इन निवेशों के माध्यम से झारखंड में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष नीति लागू कर रही है ;

(ग) क्या सरकार इस्पात क्षेत्र के विस्तार के साथ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार झारखंड में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीतियों पर विचार कर रही है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क), (ख) और (घ) : इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र की स्थापना संबंधी निर्णय कच्चे माल की उपलब्धता, बंदरगाह से दूरी, लॉजिस्टिक आदि को शामिल करते हुए तकनीकी वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने झारखंड सहित देश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार में वृद्धि हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे :-

i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।
iii. केंद्रीय बजट में अवसंरचना विस्तार पर जोर दिया गया है जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

जारी.....2/-

iv. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयात की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया।

(ग) इस्पात क्षेत्र के विस्तार के साथ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय निम्नानुसार हैं :-

i. मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक उपलब्ध कराने के लिए हरित इस्पात का वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया : रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्यों हेतु ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भावी रोडमैप प्रदान करता है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है।

iv. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

****